

सनातन संस्कृति सर्व कल्याण की सोच से जुड़ी है : राज्यपाल

पाली, (नि.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सनातन संस्कृति अपने लिए नहीं लोक कल्याण की सोच से जुड़ी है।

उन्होंने शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिव का अर्थ है, सर्व कल्याण। इसलिए इस अवसर पर हम समटा कल्याण की सोच रखते हुए कार्य करने का संकल्प लें। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृति बताते हुए कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरा है। राज्यपाल बागडे गुरुवार को पाली जिले के सादड़ी में अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ एवं स्वामी करपात्री फाउण्डेशन के तत्वावधान में आयोजित श्री नागेश्वर महादेव, श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, 12 ज्योतिर्लिंग महिमा एवं 21 कुण्डीय विलक्षण महारुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शक्ति के साथ भक्ति भाव भी देखने को मिलता है।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सादड़ी में अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ एवं स्वामी करपात्री फाउण्डेशन के तत्वावधान में आयोजित श्री नागेश्वर महादेव, श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, 12 ज्योतिर्लिंग महिमा एवं 21 कुण्डीय विलक्षण महारुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में भाग लिया।

सनातन परंपराओं एवं धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के महत्व पर बल दिया। राज्यपाल मंदिर परिसर गए जहां उन्होंने

श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु, संतों व यज्ञशाला, रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन भी किये और गाय व घोड़े को

लापसी एवं चारा भी खिलाया। इस अवसर पर बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भी विचार रखे।

सार-समाचार

एक रक्बा रसीद पर चार-चार वाहन, राजस्व हानि की लोग चर्चा कर रहे हैं

बालोतरा, (नि.सं.)। जिले में वैध बजरी लीज की आड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन का खेल चलने के आरोप सामने आ रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को लीजें से नियमों को ताक पर रखकर बजरी का दोहन किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सूत्रों के अनुसार कई स्थानों पर एक ही रक्बा रसीद (रॉयल्टी) के आधार पर कई-कई ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं डंपरों में बजरी का परिवहन किया जा रहा है। आरोप है कि एक रसीद पर चार तक गाड़ियां भरकर निकाली जा रही हैं, जबकि रिकॉर्ड में केवल एक वाहन ही दर्शाया जाता है। इससे सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी प्रभावित हो रही है और अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन-रात बजरी से भरे वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन संबंधित विभाग की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इससे खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि कुछ सफेदपोश नेताओं और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि बजरी लीजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, रक्बा रसीदों का सत्यापन किया जाए तथा अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही जीपीएस, सीसीटीवी और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाकर राजस्व चोरी पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब देखा यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या नहीं।

रिफाइनरी के उद्घाटन पर चर्चाएं तेज

बालोतरा, (नि.सं.)। आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। हालांकि सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर यह चर्चा भी तेज है कि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को आमसभा होगी या नहीं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी परियोजनाओं में शामिल पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बालोतरा जिले और पश्चिमी राजस्थान को कई विकासगतक संगतें मिल सकती हैं। वहीं आमसभा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक कार्य व सार्वजनिक नहीं होने से लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री सीधे जोधपुर रवाना होगा या आमजन को संबोधित भी करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अंतिम कार्यक्रम जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्य में को लेकर पूरे क्षेत्र की निगाहें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। क्षेत्र के लोग इसे विकास और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देख रहे हैं।

अलग थाना क्षेत्र में चार लोगों की मौत

जोधपुर, (कासं)।कमिश्नरेंट के अलग अलग थाना क्षेत्र में चार लोगों की मौत हो गई। दो लोगों ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। दो अन्य की अलग हादसे में जान गई। रातानाडा पुलिस ने बताया कि अगरचंद फतेहचंद कॉलोनी निवासी 43 साल के बबलू पुत्र कुंदनला ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। उसके पुत्र गौतम ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसी तरह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि सूज नगर शुभम मार्ट के पीछे रहने वाले 32 वर्षीय संजय पुत्र प्रकाश सांखला ने अपने घर में फंदा लगा लिया। उसके पिता प्रकाश सांखला ने मर्ग में मामला दर्ज कराया। वहीं मथानिया पुलिस ने बताया कि बड़ा कोटेचा निवासी 22 साल का कन्हैयालाल मेघवाल अपने खेत पर कार्य कर रहा था। फसल को पानी देने के लिए टय्यूबवेल चालू करते समय उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके चचेरे भाई भंवरलाल ने मर्ग में रिपोर्ट दी। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। इधर प्रतापनगर सदर पुलिस के अनुसार रमशन रोड प्रतापनगर में 40 साल का संतोष नाथ पुत्र गंगूनाथ बेहोशी की हालत में मिला। बाद में उसकी मौत हो गई। वह शराब का आदी था। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लगा पाएगा।

ऑपरेशन जागृति की दी जानकारी

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित श्याम मंदिर मे गुरुवार को पुलिस विभाग, एंटी रोमियो स्कोड एवं कालिका पेट्रोलिंग टीम की ओर से महिलाओ को विभिन्न आवश्यक हेल्प लाइन नंबर के साथ ही ऑपरेशन जागृति एवं राजकोष सिटीजन ऐप की दी जानकारी दी गई। सी.आई. जसवंत सिंह एवं एंटी रोमियो स्कोड हेड कान्स्टेबल पावती देवी एवं कालिका पेट्रोलिंग टीम सदस्य हेड कान्स्टेबल राधा, संगीता, इमरती मनोज एवं राधा ने परिभा हेल्प लाइन नंबर 1090, आपातकालीन नंबर 112, साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ये हेल्प लाईन नम्बर उनके काम के हैं इन्हें हमेशा सेव रखें। उन्होंने यातायात नियमों, सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने, सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।

जोधपुर में कई ताजिये खड़े होंगे

जोधपुर, (कासं)। पैगम्बर हजरत मोहम्मद सबसे के नवासे हजरत इमाम हसन-हुसैन सहित करबला के शहीदों की याद में मोहर्रम शुक्रवार को मनाया जाएगा। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मोहर्रम के आयोजनों के तहत आस्था के प्रतीक ताजिये खड़े किए गए हैं। आज रात शाम-ए-गरीबां (कल्ल की रात) की धीमा गीत। मोती चौक, लखारा बाजार, उम्मेद चौक, गोतलावाडी, गुलजारपुरा, खांडा फरसा, निवारियों का मोहल्ला, इस्फिकिया स्कूल, शाहों का बास, मसूरिया, खेतानाडी और सूरसागर कबीर नगर आदि क्षेत्रों में मोहर्रम ताजिये अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े किए जाएंगे।

चौहटन में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण

बाड़मेर, (नि.सं.)। जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने गुरुवार को चौहटन नगर पालिका कार्यालय में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, यूआईटी सचिव विवेक व्यास समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल एवं चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल ने लाभार्थियों से रुबर होकर शहरी सेवा शिविर में निपटारा जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधायक आदूराम मेघवाल ने आमजन से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकधिक लाभ लेने की बात कही। इस दौरान जिला कलक्टर ने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से आमजन को दी जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर एवं विधायक ने संयुक्त रूप से लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया।

शहरी सेवा शिविर में बड़ी संख्या में आमजन ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी सुरेश कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ समेत जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा आमजन उपस्थित रहे।

शिक्षक संघ शेखावत ने समस्याओं का समाधान मांगा

जालोर, (कासं)। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के एक प्रतिनिधि वरिष्ठ शिक्षक नेता सुशील पाल सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर प्रदेश के शिक्षकों, छात्रों एवं विद्यालयों से संबंधित 15 सूत्रीय ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निवारण कराने तथा दूसरा ज्ञापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम देकर पुराने शिक्षकों को टेक की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की है।

प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ शिक्षक सुशीलपालसिंह के नेतृत्व में दलपत सिंह आर्य, महासंघ के प्रतिनिधि शहजाद खान,विकेश कुमार, चंपालाल लखारा, रत्नेश्वर चौहान व दिनेश कुमार ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए ज़ब्रज्ज की अनिवार्यता को तुरंत समाप्त किया जावे, अध्यापकों (तृतीय श्रेणी शिक्षकों) के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर लंबी अघोषित रोक को हटाया जाए और लंबे समय से लंबित पदेन्रति की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे, सभी संवर्गों के लिए एक स्थाई, पारदर्शी और नीतिगत स्थानांतरण नीति लागू कर पारदर्शी तबादले करने,पे प्रोटेक्शन के नाम पर प्रदेशभर में हो रही कथित विसंगतिपूर्ण वित्तीय वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जावे। शैक्षिक कैलेंडर को व्यावहारिक बनाते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ववत (यथावत) लागू किए जाए तथा नए शैक्षिक सत्र का प्रारंभ अनिवार्य रूप से 1 जुलाई से करने, विद्यालयों में विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट वाउचर का लंबे समय से (डेड साल का) अटका हुआ बकाया भुगतान अविलंब (ब्याज सहित/त्वरित प्रभाव



जालोर में शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रतिनिधि मंडल 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचा।

से) जारी किया, प्रदेश के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त स्टाफ, निर्बाध बिजली-पानी और पर्याप्त कमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय के संकल्प को धरातल पर उतारने हेतु प्रत्येक विद्यालय में नियमित सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने, 1 अप्रैल 2026 तक की समस्त बकाया डीपीसी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जावे, एवं पदेन्रति उपरत होने वाली काउंसिलिंग में सभी रिक्त पद प्रदर्शित करन सहित 15 सूत्री ज्वलंत समस्याओं को हल करने की मांग की गई। इसी प्रकार दूसरे ज्ञापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ,भारत सरकार नई

दिल्ली को भेजा ।जिसमे बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार एक से आठ तक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षकों के लिए (अध्यापक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य है।किसी भी कानून और नियम को पीछे से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। संगठन मांग करता है कि इस मामले में सरकार उचित निर्णय कर पुराने शिक्षकों को ज़ब्रज्ज की अनिवार्यता से मुक्त कराने में प्रभावी भूमिका निभाते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान करें। अन्यथा शिक्षकों को बड़े आन्दोलन के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा,जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

एक ही दिन में 8 पात्रजनों को मिली पेंशन की मंजूरी



नगर पालिका खुडाला फालना में शहरी सेवा शिविर आयोजित हुआ।

पाली, (नि.सं.)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका खुडाला फालना द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 आमजन के लिए राहत एवं सामाजिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 8 पात्र लाभार्थियों को पेंशन कराने तथा पेंशन स्वीकृति जारी करवाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर

जारी किए गए पेंशन स्वीकृति मिलने से लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नगर पालिका खुडाला फालना के अधिशासी अधिकारी विनयपाल के निर्देशन में अनुबंध कार्मिक भंगाराम चौधरी एवं सूचना सहायक सूर्यप्रकाश ने योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आवेदनों का सत्यापन करवाने, आवश्यक दस्तावेजों प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा पेंशन स्वीकृति जारी करवाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर

योजना का लाभ मिल सका। शिविर में पीपीओ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं नगर पालिका खुडाला फालना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से अब योजनाओं का लाभ आसानी से और समयबद्ध तरीके से मिल रहा है, जिससे आमजन को राहत मिल रही है। शहरी सेवा शिविर-2026 सरकार की जनकल्याणकारी सोच को साकार करते हुए ज़रूरतमंदों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर का तबादला सही ठहराया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन लीडर के तबादले को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र कठिनाइयों के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यह मामला स्क्वाड्रन लीडर दीपक सिंधु से संबंधित था। उन्होंने जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से तेजपुर स्थानांतरण के आदेश को चुनौती दी थी। अधिकारी ने अपनी याचिका में बताया था कि उनके पिता (ब्याज बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी एक किडनी निकाली जा चुकी है। उनकी माता 50 प्रतिशत बर्न सर्वाइवर हैं और उन्हें लगातार देखभाल की आवश्यकता है। स्क्वाड्रन लीडर

स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों में तबादला सेवा का सामान्य हिस्सा है और व्यक्तिगत सुविधा, पारिवारिक कठिनाइयों के आधार पर नहीं रोका जा सकता।

सिंधु ने यह भी दलील दी थी कि पोस्टिंग नीति के अनुसार उनका जोधपुर में कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके जवाब में केंद्र सरकार और वायुसेना ने तर्क दिया कि पोस्टिंग नीति केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने संगठनात्मक आवश्यकता और संचालन क्षमता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी और जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की खंडपीठ ने अपने फैसले में माना कि अधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियां सहानुभूति योग्य हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये परिस्थितियां तबादले को रद्द करने का आधार नहीं बनतीं। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि हर मामले में व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर राहत दी जाने लगे तो इससे सशस्त्र बलों के अनुशासन और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और स्क्वाड्रन लीडर दीपक सिंधु के तबादला आदेश को बरकरार रखा।

ग्रामीण शिविर में धन्नाराम को मिली वृद्धावस्था पेंशन



पाली जिले के ग्राम पंचायत देवली पाबूजी, पंचायत समिति रानी में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुए।

पाली, (नि.सं.)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किये जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में ग्रामीणजनों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को पाली जिले के ग्राम पंचायत देवली पाबूजी, पंचायत समिति रानी में आयोजित शिविर में पात्र वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाया। ग्राम पंचायत देवली पाबूजी निवासी धन्नाराम शिविर में पहुंचे, जहां उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी प्रदान की गई। योजना की पात्रता एवं लाभों के अभावत होने पर उन्होंने तत्काल पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में उपस्थित कार्मिकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गईं तथा प्रकरण को पेंशन स्वीकृति के लिए पंचायत समिति रानी को भेजा गया। प्रशासन द्वारा

त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई तथा स्वीकृति आदेश जारी किया गया। उपखंड अधिकारी रानी शिवा जोशी ने धन्नाराम को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किया। पेंशन स्वीकृत होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से उन्हें समय पर जानकारी एवं सहायता मिली, जिससे उनकी पेंशन शीघ्र स्वीकृत हो सकी। उन्होंने राज्य सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया। 25 जून को पाली उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत वड़ेरावास रोहट के दीवांड़ी, सोजत के सांडिया व चंडावल नगर, मारवाड़ जंक्शन के शेखावास व मंडा, देसुरी के मोरवा, रानी के देवली पाबूजी, बाली के कोयलवास व भंंदर एवं सुमेरपुर के खिवांड़ी में सेवा शिविर आयोजित किए गए। शुक्रवार 26 जून को मारवाड़ जंक्शन के बांता व बिठाड़ा कलां में सेवा

शिविर का आयोजन किया जायेगा। सोमवार 29 जून को पाली उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत डेडा, रोहट के गेलावास, सोजत के चंडावल स्टेशन व करमावास पट्टा, मारवाड़ जंक्शन के मुसालिया व कण्टालिया, देसुरी के मांडपुर, रानी के सांवला, बाली के नाडिया व चामुण्डेरी रामावतान एवं सुमेरपुर के कोलीवाडा में सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। पाली उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूरना, रोहट के माण्डावास, सोजत के मण्डला व अटबडा, मारवाड़ जंक्शन के गुडा रामसिंह व ठण्णावास, देसुरी के सिन्दरली, रानी के गजनीपुरा, बाली के भीमापुर व बेडा एवं सुमेरपुर के चाणोद में सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।